(101)

संख्या– 160 /XLI-1/2012–81/11

प्रेषक,

एस0राजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
श्रीनगर (पौड़ी)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 14 ,फरवरी, 2012

विषयः– विशेष योजनागत सहायता के अन्तर्गत राजकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त पलीटेक्निक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–256/नि0प्रा0शि0/के0पो0यो0/2011–12, दिनांक 24.11.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विशेष योजनागत सहायता के अन्तर्गत **संलग्नक–1** में उल्लिखित पालीटेक्निक संस्थानों में ई–लर्निंग सेन्टर की स्थापना हेतु ₹297.32 लाख एवं **संलग्नक–2** में उल्लिखित पालीटेक्निक संस्थानों के लिए लैब उपकरण, साज–सज्जा आदि के क्रय हेतु ₹602.68 लाख तथा पालीटेक्निक संस्थानों के पुर्ननिर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु ₹100.00 लाख अर्थात कुल ₹1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नानुसार आपके निर्वतन पर रखते हुये अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख ₹में)
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	900.00
29–अनुरक्षण	100.00
कुल योग–	**1000.00**

(रूपये दस करोड़ मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय, परियोजना के सम्बन्ध में एन0आई0सी0, देहरादून के पत्र दिनांक 30.12.2011 में दिये गये परामर्शानुसार **(संलग्नक–3)** तकनीकी बिन्दुओं का समाधान किये जाने के उपरान्त, अधिप्राप्ति निमयावली, 2008 एवं अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों के आलोक में किया जायेगा।

4– उक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित पालीटेक्निक संस्थाओं के अनुरक्षण कार्यो की लागत ₹5.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में नियमानुसार आगणन गठित कराते हुये, उनका शासन स्तर पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर से यथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

5– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

क्रमशः 2.....

6– आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु स्वीकृत की जा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2203–तकनीकी शिक्षा–00–105–बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय–00–आयोजनागत–03–सामान्य पालीटेक्निक के अधीन उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित तालिका के अनुसार सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–395(P)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 06.02.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
3. निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक संस्थान उत्तराखण्ड।
6. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
9. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–160/XLI-1/2011–81/11, दिनांक 14 फरवरी, 2012 का संलग्नक–1

विशेष योजनागत सहायता के अन्तर्गत ई–लर्निंग सेन्टर की स्थापना हेतु चयनित पालीटेक्निक संस्थान का विवरण–

(1) Non-Recuring-

S.No	Name of the Polytechnic	Distirct	Amount((In Lakh)
1	G.P. Gaucher	Chamoli	14.675
2	G.P. Dwarahat	Almora	14.675
3	G.P. Srinagar	Pauri	14.675
4	G.P. Narendranagar	New Tehri	14.675
5	G.P. Uttarkashi	Uttarkashi	14.675
6	G.P. Pithuwala, Dehradun MOTHER CENTRE	Dehradun	73.82
7	G.G.P. Dehradun	Dehrad un	14.675
8	G.P. Kashipur	U.S. Nagar	14.675
9	G.P. Nainital	Nainital	14.675
10	G.P. Kotdwar	Pauri	14.675
11	G.P. Lohaghat	Champawat	14.675
12	G.G.P. Almora	Almora	14.675
13	K.L.P. Roorkee	Haridwar	14.675
	Total		**249.92**

(2) Recuring Cost for E-Learning Classes for Studio-

Sl. No.	Name of Items	Amount (In Lakh)
1-	SWAN/Board band Connection with (5Mbps)	**3.00**
2-	Studio Engineer Fee maintenance and other expenses {Annual Approx.} Including Other 12 centres	**30.00**
3-	SWAN/Board band Connection with (2Mbps)	**14.40**
	Total-	**47.40**
	Grand Total	**297.32**

(रूपये दो करोड़ सत्तानब्बे लाख बत्तीस हजार मात्र)

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–160 / XLI-1 / 2012–81 / 11, दिनांक 14 :फरवरी, 2012 का संलग्नक–2

लैब उपकरण, साज–सज्जा आदि के कय हेतु पालीटेक्निक संस्थानों का विवरण–

S.No	Name of the Polytechnic	Nature of Work	Amount (In Lakh)
1	GP Amwala (Dehradun)	Equipments for various labs. Including computer lab & workshop	30.00
2	GGP Gopeshwar	- do-	10.00
3	GGP Kotabagh	-do-	10.00
4	GP Beeronkhal(Pauri Garhwal)	-do-	30.00
5	GP Ganai Gangoli (Pithoragarh)	-do-	10.00
6	GP Vikasnagar (Dehradun)	-do-	30.00
7	GP Kotdwar (Pauri Garhwal)	-do-	20.00
8	GP Sahiya (Dehradun)	-do-	30.00
9	GP Garhi Shyampur (Dehradun)	-do-	40.00
10	GP Haridwar	-do-	30.00
11	GP New Tehri	-do-	20.00
12	GP Malla Salam	-do-	5.00
13	GP Jakholi, Rudraprayag	-do-	5.00
14.	GP Kanalichhina	-do-	15.00
15.	GP Kanda	-do-	24.00
16.	GP Satpuli	-do-	24.00
17.	GP Kaladungi	-do-	20.00
18.	GP Chaunliya	-do-	5.00
19.	GP Didihat	-do-	5.68
20.	GP Garur (Bageshwar)	-do-	20.00
21.	GP Rudraprayag	-do-	10.00
22.	GGP Almora	-do-	35.00
23.	GGP Dehradun	-do-	30.00
24.	GP Kashipur	-do-	52.00
25.	GP Srinagar	-do-	40.00
26.	GP Dehradun	-do-	52.00
Total			**602.68**

(रूपये छः करोड़ दो लाख अड़सठ हजार मात्र)

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

संलग्नक -3

National Informatics Centre
State Unit, Schivalaya
Dehardun

Annexure-1

Comments/Suggestion on "Proposal for E-learning facility at 13 Polytechnics" - Uttarakhand.

This refers to proposal received from Dept of Technical Education, Uttarakhand, titled as "Centrally sponsored scheme: Special Planning Aid for strengthening of Polytechnics" for NIC's suggestions as per noting of Dept of Finance, GoUK.

2. NIC had a brief discussion with Sri Kanyal, Deputy Director of concerned department, Additional Secretary (TE) and Principal Secretary (TE) regarding need and perspective of proposal.

3. At conceptual level, it is highly recommended to take initiative for setting up E-learning centres in 13 polytechnics which have been selected by Department.

4. In order to fulfill this objective, Dept of TE has worked out a very broad proposal towards submission for SPA under Centrally sponsored scheme based upon technical inputs from various polytechnics and their own resources. Based upon their approach and information, a bill of material and cost estimates have been complied for setting up e-learning centers in in 13 polytechnics (Capital + Recurring expenditure) for seeking financial support of Rs. 10.0 Cr from Central share and remaining from state share.

5. At this stage, proposal appears to be merely a perspective plan along with broad estimates. **It is strongly recommended that prior to execution of proposal, department should work out a technical proposal comprising following points:**

a. Feasibility of network connectivity at each site along with bandwidth requirement. In current proposition, it is mentioned that 2-5 mbps requirement per site would be catered from SWAN/Broadband with help of BSNL. At present, total shareable bandwidth at District to taluka level is only 2 Mbps for E_Governance services. Dept of TE may like to discuss various technical requirements, network-resources availability and Govt's sanctions regarding its usage, service policy, discounts for educational institutes with Dept of IT , GoUK and BSNL respectively.
b. For each E-learning proposition such as web-learning, virtual class rooms etc. etc. , separate feasibility based bill of material may need to worked out with help from professional agency prior to floating RFP. Such bill of material should be vendor and brand neutral.
c. As far as possible, Open Standards should be adopted for application s/w, system s/w with proper AMC. Polytechnics being technical institutes

should be able to adhere to Open standard policy. This will cut down CAPEX and OPEX considerably.

d. Proper SLAs and MOUs may need to be signed for consistent usage of proposed facility and to ensure that intent and objective is fulfilled as desired.

Department of TE , GoUK may need to seek approval from State level technical committee under chairmanship of Principal Secretary (IT), GoUK prior to execution of proposal. **This may kindly be noted that NIC's comments are only regarding technical aspects of proposal.**

D.R.Shukla 30/12/:

(D.R.Shukla)
SIO, NIC-UK